असंगठित कामगारों के लिए कानून विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी

किसान आत्महत्या का मुद्दा उठाएगी मेधा

नागपुर में असंगठित कामगारों के तीन दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करती मनोज कालडा आयोजन की तैसी पेखा पालकर।

नागपुर, ८ अक्टूबर (प्रतिनिधि)

अपने ही एक सीनियर से चल रहे अंतरिम रोज कंपनी के कर्मचारी का संघर्ष अब संसद में विधेयक प्रस्तुत करने की आवाजबन्द जाएगा। मेधा पाटकर ने आयोजित इस सम्मेलन में यह घोषणा की। इसके लिए संसद में कई सांसदों से बातचीत हो चुकी है। सम्मेलन में 'विधेयक' में शामिल करने के लिए सम्मेलन में अनेक सुझाव रखे गए। साथ इसके लिए जनआंदोलन खड़ा करने की घोषणा भी सम्मेलन में किया की गई। यहां दूरी प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषय कि उक्त राज्य सभी को विधेयक का रूप देने पेश राज्य, ने लगातार आंदोलन करेंगे। सम्मेलन के प्रमुख अतिथि राज्य के नेताओं सांसदों प्रतिनिधियों ने उपस्थि जर्ज ।।।।। के बाद राज्य के पूर्व आदिवा. आय सांसदों सामाजिक कार्यकर्ताओं को पीपल का आयोजन किया. जो कार्यकर्ता ने कहा कि जिसे आंदोलन में ।.८ करोड़ असंगठित कामगार है.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि देश में असंगठित कामगारों की संख्या ९४ करोड़ से अधिक है. ये लोग एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं. सामाजिक अधिकारों के प्रति इनके लिए सुरक्षात्मक कानूनों का अभाव है. विधेयक को 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद' के जरिए तैयार किया गया है. लेकिन इसमें कई खामियां हैं. सम्मेलन में अनेक सुझाव रखे गए हैं. यह जनआंदोलन खड़ा करने की घोषणा भी सम्मेलन में किया की गई। यहां दूरी प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषय कि उक्त राज्य सभी को विधेयक का रूप देने पेश राज्य, ने लगातार आंदोलन करेंगे। सम्मेलन के प्रमुख अतिथि राज्य के नेताओं सांसदों प्रतिनिधियों ने उपस्थि जर्ज ।।।।। के बाद राज्य के पूर्व आदिवा. आय सांसदों सामाजिक कार्यकर्ताओं को पीपल का आयोजन किया. जो कार्यकर्ता ने कहा कि जिसे आंदोलन में ।.८ करोड़ असंगठित कामगार है.

नागपुर, ८ अक्टूबर (प्रतिनिधि)

अपने कार्यकाल आंदोलन की ऐसी किसान आत्महत्या के मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा है कि वे आंदोलन की ओर से पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगी और उनके दुःख में शामिल होंगी। मेधा पाटकर ने यह घोषणा रविवार को यहां आयोजित तीन दिवसीय असंगठित कामगार सम्मेलन के समापन सत्र में की। उन्होंने कहा कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। इसके लिए संसद में कई सांसदों से बातचीत हो चुकी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुका है। इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। इसके लिए कृषि मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मेधा पाटकर ने कहा कि कई लोग आत्महत्या को कायरता कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुका है। इसके लिए कृषि मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

सम्मेलन में राज्य भर से कार्यकर्ता मौजूद थे। मेधा पाटकर ने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाने की घोषणा करे। इसके लिए संसद में कई सांसदों से बातचीत हो चुकी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुका है। इसके लिए कृषि मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।